



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 844 राँची, मंगलवार 10 अग्रहायण, 1937 (श०)
1 दिसम्बर, 2015 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-26/2015-143-लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राज्यपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2015 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2015

(झारखंड अधिनियम, 22, 2015)

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में संशोधन हेतु अधिनियम

प्रस्तावना: -

चूँकि, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठन के साथ सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से समितियाँ अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रूप में कार्य कर सकेंगी;

और, चूँकि, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी आवश्यकता हो;

और, चूँकि, संविधान के सन्तानवे संशोधन अधिनियम, 2011 के आलोक में झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 में कई संशोधन आवश्यक हैं;

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ: - (1) यह अधिनियम झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा-2 का संशोधन।- झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 में निम्नलिखित संशोधन की जायेगी, यथा:-

उपधारा (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी; यथा:-

(ख) “बोर्ड” से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, जिस नाम से भी उसे अभिहित किया गया हो, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो;

3. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा-2 के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-2 की उपधारा-(त) के बाद निम्नलिखित उपधारा-(थ) जोड़ा जायेगा, यथा (थ) “शीर्ष समिति” से अभिप्रेत है, सहकारी समिति जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य हो अथवा अन्य कोई सहकारी संघ/परिसंघ जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में हो और जिसे सहकारी समिति के निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में घोषित किया गया हो।

4. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा-2 के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-2 की उपधारा-(थ) के बाद निम्नलिखित उपधारा-(द) जोड़ा जायेगा, यथा (द) **“क्रियाशील निदेशक”** से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विनिर्दिष्ट समिति के क्रियाशील कार्यपालक निदेशक।

5. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-23 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-23 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे, यथा:-

(क) उपधारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:- (7) सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया कोई भी व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों, जिसमें मताधिकार भी शामिल है, का प्रयोग सहकारी समिति की उपविधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबन्धन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम उपस्थिति तथा समिति द्वारा प्रदत्त सेवाओं के न्यूनतम स्तर तक उपयोग के बाद ही करेगा;

परन्तु कोई व्यक्ति कम से कम एक वर्ष तक सदस्य बने रहने के बाद ही मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होगा;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तु किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रथम वर्ष में प्रवर्तक सदस्य पर लागू नहीं होगा।

6. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (झारखण्ड अधिनियम 2, 1997) की धारा-23 (7) के बाद अन्तस्थापन। झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 की धारा-23 की उपधारा (7) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएँ (8), उपधारा (9) तथा उपधारा (10) जोड़ी जायेगी, यथा-

(8) प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक सदस्य को ऐसे सदस्य के साथ उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक पहुँच के लिए उपबन्ध करेगा।

(9) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों के लेखाओं के सम्बन्ध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त कर सकेंगे। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक/प्रबन्धक सदस्य को सभी वांछित जानकारी/कागजात सुगम करायेंगे।

(10) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली या उपविधियों में विहित प्रावधानों के अधीन शिक्षा तथा सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-25 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-25 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, यथा:-

(क) उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

(1) अधिनियम तथा उपविधियों के उपबंधों के अधीन किसी सहकारी समिति का अंतिम प्राधिकार इसके सामान्य निकाय में निहित होगा। प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर उपधारा (3) के अध्यक्षीन सभी अथवा किसी विषय पर विचार किया जायेगा।

(ख) उपधारा (3) (क) एवं (ख) विलोपित की जायेगी।

8. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-26 की उपधारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

(2) बोर्ड का आकार उपविधियों के अनुसार पदधारियों सहित अधिकतम इक्कीस सदस्यों का होगा। मुख्य कार्यपालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। समिति के बोर्ड में बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त अथवा समिति के उद्देश्यों और कार्यकलाप के अनुरूप अन्य क्षेत्रों के विषिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सदस्य के रूप में बोर्ड द्वारा सहयोजित किया जायेगा।

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और ये बोर्ड की कुल संख्या से अतिरिक्त होगा।

परन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसी सदस्यता के कारण मत देने का अधिकार नहीं होगा और न वे बोर्ड में पदधारी के रूप में निर्वाचित हो सकेंगे।

परन्तु यह और कि सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गणना बोर्ड की कुल संख्या में नहीं की जायेगी;

परन्तु और भी कि प्रत्येक सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। उस 50 प्रतिशत आरक्षित स्थान में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए दो स्थान वैसी समितियों में आरक्षित होंगे, जिन समितियों में उक्त वर्ग या कोटि से सदस्य होंगे। इस प्रकार

से आरक्षित स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला का पद निर्वाचन या/और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे।

9. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-28 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-28 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

28. पदावधि - किसी सहकारी समिति की बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदधारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदधारियों की पदावधि बोर्ड के पदावधि का सहविस्तारी होगा;

परन्तु बोर्ड में किसी कारणवश हुई रिक्ति को बोर्ड द्वारा उन्ही वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भरा जायेगा, जिन से सम्बन्धित आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड की पदावधि इसकी मूल पदावधि से आधे से कम बाकी हो;

परन्तु यह और कि किसी सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो, और बोर्ड में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि के लिए सहकारी समिति द्वारा विशेष आम सभा में उपनिर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा;

परन्तु यह और भी कि प्रथम बोर्ड की कार्यावधि सहकारी समिति के निबन्धन की तारीख से लेकर बारह माह से अधिक की नहीं होगी।

10. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-29 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-29 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, यथा:-

(क) उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

(1) सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी पदधारी बोर्ड की होगी।

(ख) उपधारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

(2) निर्वाचन, पदावरोही निदेशक की पदावधि समाप्ति के पूर्व झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन सहकारी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संचालित किया जायेगा।

(ग) उपधारा-(3) विलोपित की जायेगी।

11. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-33 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-33 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे, यथा:-

(1) सहकारी समिति अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा अंकेक्षक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबन्धक के कार्यालय का होगा। निबन्धक, सहयोग समितियाँ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक की न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव का निर्धारण समय-समय पर किया जाएगा। केवल ऐसे अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण करने हेतु योग्य होंगे।

(ख) उपधारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

(4) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त उपधारा (1) में सन्दर्भित अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा की जायेगी। अंकेक्षक के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा किया जायेगा, जो निबन्धक द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

(ग) उपधारा (10) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (11) जोड़ी जायेगी, यथा:-

(11) शीर्ष सहकारी समिति के द्वारा अपने लेखाओं के लेखा परीक्षण के उपरान्त लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन समिति के सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा ताकि उक्त रिपोर्ट को राज्य सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित की गई प्रक्रिया के अधीन विधान मण्डल के पटल पर रखा जा सके।

12. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-35 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-35 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

35 वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना: - प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषयवस्तु सन्निहित रहेंगे:-

(क) कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट,

(ख) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण,

(ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटाव हेतु योजना,

(घ) सहकारी समिति की उपविधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो,

(ङ) निर्वाचन यदि देय हो, तथा सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख से संबंधित घोषणा,

(च) निबन्धक द्वारा संसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के पालन हेतु आवश्यक, कोई अन्य सूचना ।

13. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-41 के बाद नई धारा-41क का अन्तःस्थापन: - उक्त अधिनियम की धारा-41 के बाद निम्नलिखित नई धारा-41क अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:-

41क. अधिकरण द्वारा बोर्ड का अवक्रमण: - (1) सहकारी समिति के सदस्य द्वारा दिये गये आवेदन पर यदि अधिकरण की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड जिस सहकारी समिति में राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी गई हो अथवा ऋण के लिए गारंटी दी गई हो, लगातार ऋण अदायगी में चूक की हो अथवा इस अधिनियम, नियमावली या उपविधियों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही की हो या सहकारी समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल कार्य की हो या बोर्ड के गठन अथवा कार्यकलाप में गतिरोध हो या झारखण्ड राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के अधीन निर्वाचन के संचालन में असफल हो जाये, तो उस सहकारी समिति के बोर्ड को अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कारणों सहित लिखित आदेश द्वारा सहकारी समिति के बोर्ड को अधिकतम छह माह के लिए अधिक्रमित कर सकेगी और आदेश दे सकेगी कि इसके सभी अथवा कोई सदस्य आदेश में विहित कालावधि पाँच वर्ष से अनधिक तक के लिए सहकारी समिति के बोर्ड में निर्वाचन के लिए अयोग्य होंगे। निबन्धक इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को अभिलिखित करेंगे और निबन्धित डाक से सम्बन्धित सहकारी समिति को सूचित करेंगे;

परन्तु कि ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिंग कारोबार कर रही हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे;

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाले ऐसी सहकारी समिति के मामले में बोर्ड के अवक्रमण की अवधि एक वर्ष की होगी

परन्तु और भी कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के मामले में बोर्ड का अवक्रमण रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

(2) जब कोई सहकारी समिति उपधारा (1) के अधीन अधिक्रमित की जायेगी तो अधिकरण सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करेगी। नियुक्त प्रशासक इस उपधारा के अधीन विनिर्धारित अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु सभी आवश्यक उपाय करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को समिति के प्रबन्ध का कार्यभार सौंप देंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक को सहकारी समिति के कार्य संचालन के लिए अधिकरण द्वारा ऐसा पारिश्रमिक निर्धारित किया जायेगा जो वह उचित समझे। निर्धारित पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतये होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, अधिकरण द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अधीन कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उपविधियों में बोर्ड को प्रदत्त सभी कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करेंगे;

परन्तु अधिकरण को अवक्रमण की अवधि में प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी।

14. झारखण्ड अधिनियम 2, 1997 की धारा-42 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-42 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि -

(क) एक सहकारी समिति अथवा सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाये या मिथ्या सूचना दे अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निबन्धक को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर जानबूझकर कोई सूचना नहीं दें, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तिसंगत सफाई के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करें, अथवा

(ग) कोई नियोक्ता बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को कटौती की तिथि से चैदह दिनों के भीतर एक सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल हो, अथवा

(घ) कोई सहकारी समिति का कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक अपने अभिरक्षा में रखनेवाली सहकारी समिति के पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों का प्रभार अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल हो, अथवा

(ङ) कोई भी व्यक्ति सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्यों अथवा पदधारियों के निर्वाचन के पूर्व, निर्वाचन के दौरान अथवा पश्चात् भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो ।

15.

अध्याय 10 क

सहकारी बैंक

48-क- अध्याय का सहकारी बैंकों पर लागू होना:- (1) इस अध्याय के उपबन्ध निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इंश्योरेंस कॉपोरेशन एक्ट), 1996 (47ए 1961) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक पर, इस अधिनियम के अन्य भागों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त, लागू होंगे। जहाँ प्रकट अथवा विवक्षित अन्य असंगति का कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहाँ इस आशय के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य भागों के उपबन्धों पर प्रभावी होंगे।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, निक्षेप बीमा निगम से तात्पर्य है- निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47, 1961) की धारा 3 के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा निगम और रिजर्व बैंक से तात्पर्य है- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 (2, 1934) के अधीन स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

48-ख- विभाजन, समामेलन, समझौता आदि:- (1) किसी सहकारी बैंक के बारे में समझौता या व्यवस्था या उसके समामेलन या पुनर्निर्माण अथवा उसकी आस्तियों और दायित्वों के विभाजन या अंतरण की कोई स्कीम मंजूरी करने के आदेश रिजर्व बैंक की पूर्वलिखित मंजूरी के बिना न दिया जाएगा।

(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के सम्बन्ध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम (बैंकिंग रेगुलेशन्स एक्ट) 1949 (10, 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया हो, वहाँ रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के पूर्वलिखित अनुमोदन से अधिस्थगन की अवधि में निम्नलिखित स्कीम तैयार करा सकेगा:-

(i) सहकारिता बैंक के पुनर्निर्माण के लिये, या

(ii) किसी अन्य सहकारिता बैंक (इसमें आगे "अंतरिती बैंक" के रूप में निर्दिष्ट) के साथ उसके समामेलन के लिये।

(3) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि कोई सहकारिता बैंक जो निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेन्स कॉपोरेशन ऐक्ट), 1961 (47, 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था अथवा पुनर्निर्माण की कोई स्कीम मंजूर की गई हो और निक्षेप बीमा निगम, उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने का भागी हो गया हो, तो ऐसा समामेलन के बाद गठित नया सहकारिता बैंक

अथवा, यथास्थिति बीमाकृत या अंतरिती बैंक, उस अधिनियम की धारा 21 में निर्दिष्ट परिस्थितियों में, सीमा तक और रीति से, निक्षेप बीमा निगम को प्रतिसंदत करने की मध्यता के अधीन होगा।

48-ग- सहकारी बैंको की प्रबन्ध समिति का अवक्रमित किया जाना:- इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, यदि इसकी अपेक्षा रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में लोकहित में अथवा किसी सहकारी बैंक के काम-काज की निक्षेपकर्ताओं के हित में अहितकर होने देने से रोकने के लिये या सहकारी बैंक का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये की जाय तो रजिस्ट्रार, ऐसी शर्तों पर और कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, उस सहकारी बैंक की प्रबन्धक समिति या अन्य प्रबन्ध निकाय को (चाहे वह जिस किसी नाम से भी कहा जाय) अवक्रमित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित करेगा।

48-घ- परिसमापन आदेश के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा:- (1) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना परिसमाप्त नहीं किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निक्षेप बीमा निगम अधिनियम (डिपोजिट इन्श्योरेंस कांरपोरेशन ऐक्ट), 1961 (47, 1961) की धारा 13-घ में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक द्वारा यदि रजिस्ट्रार से वैसी अपेक्षा की जाय तो वह किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश देगा।

48-ड.- निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति:- जहाँ कोई सहकारी बैंक निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 (47, 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमाप्त हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने की दायी हो जाए तो निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा 21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिपूर्ति की जायगी।

48-च- रिजर्व बैंक की मंजूरी या अध्यपेक्षा की अंतिमता:- इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी जहाँ रिजर्व बैंक की पूर्व लिखित मंजूरी से या उसके द्वारा अध्यपेक्षा करने पर -

- (i) किसी सहकारिता बैंक के परिसमापन का आदेश दिया जाय, या
- (ii) उसके सम्बन्ध में समझौता या व्यवस्था या पुनर्निर्माण या समामेलन की स्कीम बनाई जाय, या

(iii) उसके सम्बन्ध में उसकी प्रबन्धक समिति किसी अन्य प्रबन्ध निकाय (चाहे जिस किसी नाम से भी कहा जाय) के अधिष्ठापन और उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति का आदेश दिया जाय, वहाँ इसके विरुद्ध न तो कोई अपील पुनरीक्षण अथवा पुनर्विलोकन किया जायगा और न वह अनुज्ञेय ही होगा तथा रिजर्व बैंक की ऐसी मंजूरी या अध्यपेक्षा पर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2015

संख्या-एल०जी०-26/2015-144-लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक-07/11/2015 को अनुमत झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

The Jharkhand Self Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015
(Jharkhand Act 22, 2015)

An Act to amend the Jharkhand Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996

Preamble:

Where as, voluntarily constituted Co-operative Societies can lead to the socio-economic betterment of their members as based on their economic participation, democratic control and autonomous functioning so as to act more meaningfully in the interests of their members;

And where as it is an obligation of the State Government to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the Co-operative Societies in the State and promote them and take such measures as are necessary for this purpose;

And where as in pursuance of the 97th amendment Act of the constitution of India many amendments are imperative in the Jharkhand Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996.

Be it enacted by the Governor of Jharkhand in the 66th year of the Republic of India as follows: -

- 1. Short title, extent and commencement.** – (1) This Act may be called the Jharkhand Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.
 (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
 (3) It shall come into force at once.
- 2.** Amendment in subsection (b) of Section - 2 of the Act 2 of 1996 – Subsection (a) of Section 2 of the Jharkhand Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 shall be substituted by the following, namely–
 (b) **“Board”** means Board of Directors or Governing Body or Managing Committee by whatever name it is called to which the direction and control of the management of the affairs of a Co-operative Society is entrusted to;
- 3.** Insertion after sub-section (p) of section 2 of the Act 2 of 1996 – The following subsection (q) shall be added after the subsection (p) of section 2 of the Jharkhand Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996, namely **“Apex Society”** means a Co-operative Society whose area of operation covers whole of Jharkhand or any Co-operative federation/union having in its area of operation whole of Jharkhand and which has been declared as Apex Society by the Registrar of Co-operative Societies;
- 4.** Insertion after subsection (q) of section 2 of the Act 2 of 1996 – The following subsection (r) shall be added after the subsection (q) of subsection 2 of the Jharkhand Co-operative Act, 1996 namely **“Functional Directors”** means functional executive directors of the society specified as per rules or Bye-laws of that co-operative society;

5. Amendment in subsection (7) of section 23 shall be substituted by the following:

“A person admitted as a member may exercise the rights of membership, including the right to vote only after ensuring minimum attendance, as required in the meetings convened for participation in the management of the society and availing of minimum requisite services of the society as may be prescribed in the bye-laws of the society;

Provided that a person shall have been a member for at least one year before being eligible to exercise the right to vote;

Provided further that the above provision shall not apply to the promoter members in the first year of registration of a Co-operative Society.”

6. After subsection (7) of section 23 the following sub-sections (8), (9) and (10) shall be inserted, namely:

“(8) Every Co-operative Society shall provide access to every member to the books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business with such member.

(9) Every member of a Co-operative Society shall have the right to get all information/ documents regarding books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business. The chief executive officer/manager of the Co-operative Society shall ensure access to every member to all required information/documents.

(10) The members of any Co-operative Society shall have the right to get education and co-operative related training as per the rules or bye-laws made under any provisions of this Act.”

7. In the said Act section - 25 shall be amended as follows, namely –

(a) Sub-section (1) shall be substituted by the following, namely -

“(1) Subject to the provisions of this Act and the bye-laws the ultimate authority of a Co-operative Society shall vest in its general body. Board of every Co-operative Society shall convene annual general meeting within six months from the closure of financial year, which shall deal with all or any matter dealt with subsection (3) except those in relation to the election of members and office-bearer of the Board.”

(b) Sub section (3)(a) and (b) shall be deleted.

8. In the said Act sub-section 2 of section - 26 shall be amended as follows, namely –

“(2) The Board shall consist of maximum twenty one members including office-bearers in accordance with the bye-laws. Chief Executive shall be an ex-officio member of the Board. The Board shall co-opt such persons having experience in the field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the object and the activities under taken by the Co-

operative Societies, as members of the board; provided that the number of such co-opted members shall not exceed two and this shall be in addition to the total members of the board;

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the Co-operative Society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board;

Provided further also that the functional directors of a Co-operative Society shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors;

Provided that at least 50 percent seats of managing board shall be reserved for the women members, out of which two seats shall be reserved for the scheduled castes or Scheduled Tribes women in the board of every Co-operative Society consisting of individuals as members and having members from such class or category of persons.

The seats so reserved shall be filled up from amongst the members of scheduled castes or scheduled tribes women members either by election or/ and by co-option.”

9. In the said Act section - 28 shall be amended as follows, namely –

The term of office of elected members of the board and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the board;

Provided that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of the board is less than half of its original term.

Provided further that the term of the first board shall not exceed twelve months from the date of registration of the Co-operative Society.”

10. In the said Act sub-section (1), (2) & (3) of section - 29 shall be amended as follows, namely –

“(1) The conduct of elections to the board of a Co-operative Society shall be the responsibility of the incumbent board.

“(2) The election shall be conducted before the expiry of term of the outgoing director in the manner specified in the bye-laws and the provisions made there under and as per the provisions of the Jharkhand Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 and rules made there under.”

Subsection (3) shall be deleted.

11. (a) Subsection (1) shall be substituted by the following, namely -

“(1) A Co-operative Society shall get its accounts audited by an auditor from a panel approved by Registrar, co-operative societies or by the authority authorized by him. at least once in every financial year. Such Auditor shall either be a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 or from the office of the Registrar. The minimum qualification and experience of auditors and Chartered Accountant firm in the panel approved by the Registrar, co-operative societies or authorized by him shall be determined from time to time. Only such Auditor or Chartered Accountant firm shall be eligible for the audit of the accounts of Co-operative Society.”

(b) Subsection (4) shall be substituted by the following, namely -

“(4) The audit of the accounts of every Co-operative Society shall be done by the auditor or Chartered Accountant firm, specified under sub-section (1), appointed by the General Body of Co-operative Society. The remuneration of the auditor shall be fixed by the General Body in terms with the audit fee fixed by the Registrar;

(c) After subsection (10) following new subsection (11) shall be inserted as follows –

“(11) Apex Co-operative Society with the approval of general body shall compulsorily submit the audit report after the audit of the statement of accounts to the Registrar within thirty days so that the report may be placed in the Legislature through State Government in accordance with the procedure laid down by the State Government for this purpose.”

12. In the said Act Section - 35 shall be substituted by the following, namely -

“35. Filing Annual statements of Accounts. - Every Co-operative Society shall file annual statement of accounts before the Registrar within six months of the end of financial year which shall include following subjects:

- (a) Annual report of the activities.
- (b) Audited statement of accounts.
- (c) Plan to deal with the surplus as approved by general body.
- (d) List of the amendments done, if any, in the bye-laws of the Co-operative Society.
- (e) Declaration regarding date for the conduct of election, if due, and date for the holding of its general body meeting.
- (f) Any other information, by the Registrar in pursuance of any of the provisions of the act.

13. Insertion of section - 41A after section - 41 of the Jharkhand Act 2 of 1997. – In the said Act after section - 41 the following new Section - 41A shall be inserted, namely -

“41A. Supersession of the Board by the Tribunal. - (1) If upon the receipt of application from the member of a Co-operative Society, the tribunal is of the opinion that the Board of any Co-operative Society, where loan or financial aid has been provided by the State Government or loan has been provided on Government guarantee, is persistently making defaults or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act, the Rules or the bye-laws, or conducting business against the interest of its members or there is stalemate in the formation or functioning of the Board, it may, after giving opportunity to the managing committee to state its objection, if any, by order with reasons in writing supersede the Board of the Co-operative Society for a period not exceeding six months. The members of the boards of societies so superseded shall not be eligible for reelection for five years from the date of supersession. Registrar shall record every order passed under this section in writing and inform the concerned Co-operative Society through registered post;

Provided that in case of Co-operative Society carrying on the business of banking, provisions of Banking Regulation Act, 1949 shall also apply;

Provided also that in case of Co-operative Society carrying the business of banking the maximum period of dissolution shall be of one year;

Provided that the dissolution of the Board of the Co-operative Society having banking operation shall be done in consultation with the Reserve Bank of India.

(2) When any Co-operative Society is under supersession under sub-section (1), the Tribunal shall appoint an Administrator to conduct the affairs of the society. The Administrator appointed under this sub-section, shall take necessary action for the election of the Board of Co-operative Society within the specified period and shall hand over the management to elected Board.

(3) The Administrator appointed under sub-section (2) shall get remuneration, as may be fixed by the Tribunal, as it deems fit to carry on the business of the Co-operative Society. The remuneration so fixed shall be payable from the accounts of Co-operative Society.

(4) Administrator appointed under sub-section (2) shall work in accordance with the service conditions laid down by the Tribunal and shall perform all the duties and carry on responsibilities assigned to the Board under this Act, rules and the bye-laws;

Provided that the Tribunal shall have the power to change the Administrator during the period of supersession.”

14. In the said Act subsection (1) of section - 42 shall be substituted by the following, namely:-

“ (1) It shall be an offence under this Act if-

(a) A Co-operative Society or an officer or member thereof wilfully furnishes a false return or false information, or does not furnish wilfully any information required from him by a person authorized in this behalf under the provisions of this Act;

(b) any person wilfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of this Act;

(c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative Society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;

(d) any officer or custodian who wilfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a Co-operative Society of which he is an officer or custodian, to an authorized person; and,

(e) any person indulges in corrupt practices before, during or after the election of the office bearer or member of the Board of the Co-operative Society.”

15. Insertion of new chapter-X- A after chapter- X comprising of section 48A to 48F of the Act 2 of 1997. – In the said Act, after chapter X the following new chapter-X- A shall be inserted, namely –

CHAPTER-X- A

48A. Application of the Chapter to cooperative Bank. – (1) The provisions of this chapter shall apply to a Cooperative Bank as defined in the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) in addition to the provisions contained in other parts of this Act, Where any question of apparent or implied inconsistency arises, the provisions of this Chapter shall prevail over the provisions of the other parts of this Act.

(2) For the purposes of this chapter, “Deposit insurance corporation means the Deposit insurance corporation established under the Deposit Insurance Corporation Act, 1961) and “Reserve Bank’ means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)

48B. Division, amalgamation, compromise, etc. – (1) No order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or of amalgamation or reconstruction or of division

or transfer of assets and liabilities of a Cooperative Bank shall be made without the previous sanction in writing of the Reserve Bank.

(2) Where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949(10 of 1949) in respect of a Cooperative Bank, the Registrar, with the previous approval of the Reserve Bank in writing, may during the period of moratorium, prepare a scheme,-

(i) for the re-construction of the Cooperative Bank; or

(ii) for its amalgamation with any other Cooperative Bank (herein referred to as the transferee Bank).

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act where a Cooperative Bank being an insured bank within the meaning of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) is amalgamated or in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction has been sanctioned and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank, under sub-section (2) of section 16 of the Act, the bank with which such insured bank is amalgamated or, the new Cooperative Bank formed after such amalgamation or, as the case may be, the insured bank or the transferee bank shall be under an obligation to repay the Deposit Insurance Corporation in the circumstances, to the extent and in the manner referred to in section 21 of that Act.

48C. Supersession of Managing Committee of Cooperative Bank. – Notwithstanding anything contrary contained in this Act, Registrar shall, if so required in writing by the Reserve Bank in public interest or for preventing the affairs of the Cooperative Bank being conducted in a manner detrimental to the interests of the depositors or for securing the proper management of the Cooperative Bank; pass an order for the supersession of the managing committee or other managing body (by whatever name called) of

that Cooperative Bank, appoint an administrator, upon such terms and for such periods not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank.

48D. Reserve Bank's sanction or requisition for winding up order. – (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no Cooperative Bank shall be wound up except with the previous sanction in writing of the Reserve Bank.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Registrar shall make an order for the winding up of a Cooperative Bank if so required by the Reserve Bank in the circumstances mentioned in section 13 D of the Deposit insurance Corporation Act, 1961

(47 of 1961)

48E. Reimbursement to Deposit Insurance Corporation. – Where a Cooperative Bank, being an insured bank within the meaning of Deposit Insurance Corporation Act, 1961 (47 of 1961) is wound up or is taken into liquidation and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay to the depositors of the insured bank under sub-section (1) of section 16 of that Act, the Deposit Insurance Corporation shall be reimbursed in the circumstances to the extent and in the manner provided in section 21 of that Act.

48F. Finality of the Reserve Bank's sanction or requisition. – Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act where with the previous sanction in writing or on the requisition of the Reserve Bank-

- (i) an order for the winding up of the cooperative bank is made, or
- (ii) in respect of which a scheme of compromise or arrangement or of reconstruction or amalgamation is made, or
- (iii) in respect of which an order for the supersession of its managing committee or other managing body (by whatever name called) and the appointment of an administrator therefore has been made.

no appeal or revision on review there against shall lie or be permissible and such sanction or requisition of the Reserve Bank shall not be liable to be called in question in any manner.]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी० बी० मंगलमूर्ति,
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
 विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।
